सफलता 'मंथन' की, क्रमशः .....

सीहोर। सीहोर जिले के अमलाहा गाँव के निवासी अनिल कुमार ने बताया कि उसने सत्र 2011-12 में मंथन आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की परीक्षा उत्तीर्ण की और वह अब सहकारी समिति में कार्यरत है। अपनी इस सफलता का श्रेय वह मंथन आईटीआई को देता है। तथा अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छे से कर पा रहे हैं। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय मंथन आईटीआई के शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

जिलों से

● रिपोर्टर

इनोवा कार में हिरण के मांस की तस्करी, भोपाल से ले जा रहे थे मुंबई; 3 आरोपी अरेस्ट

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में वन विभाग की टीम ने हिरण के मांस की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग की टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इनोवा गाड़ी से हिरण के मांस की तस्करी करने वाले मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए तीनों आरोपी मूल रूप से मुंबई के रहने वाले है। वन विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग इनोवा कार में अवैध तरीके से बड़ी मात्रा में हिरण का मांस लेकर इंदौर की ओर आए हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर संदिग्ध इनोवा गाड़ी के बारे में वन विभाग की तरफ से तफ्तीश की गई और इनोवा गाड़ी को किशनगंज टोल नाके पर पकड़ा। गाड़ी के पकड़े जाने के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो उसमें हिरण का मांस मिला। वन विभाग की टीम ने गाड़ी को जब्त कर लिया।

वन विभाग की टीम ने गाड़ी को जब्त करने के बाद उससे बरामद हिरन के मांस को जांच के लिए भेज दिया है। वन विभाग की टीम ने बताया कि जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। वहीं प्रारंभिक जांच में वन विभाग टीम ने आशंका जताते हुए कहा कि हिरण का मांस भोपाल से लाया गया और मुंबई इसकी डिलीवरी देने के लिए आरोपी जा रहे थे। वहीं वन विभाग की टीम ने इस पूरे मामले में जोहर हुसैन, सलमान ,इलियाज को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के देते हुए वन विभाग की टीम ने बताया कि सभी आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारी काफी बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि जल्द ही इस पूरे मामले में कुछ और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

लगाए आरोप

1760 बीमारियों का इलाज निजी अस्पतालों में करवाने की सुविधा सरकार ने दी लेकिन कुछ शिकायतों के बाद सरकार ने 196 बीमारियों को इलाज वाली सूची से अब हटा दिया

कमलनाथ बोले-सफेद हाथी साबित हो रही आयुष्मान योजना, सूची से हटाई गई 196 बीमारियों को शामिल करने की मांग

● मंथन संवाददाता

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आयुष्मान भारत योजना को सफेद हाथी करार दिया है, कमलनाथ ने इस योजना में शामिल बीमारियों की सूची से 196 बीमारियों को हटाने पर ऐतराज जताते हुए इसे वापस सूची में शामिल करने की मांग की है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाये हैं, उन्होंने इसे सफेद हाथी करार दिया है, कमलनाथ ने इस योजना में शामिल बीमारियों की सूची से 196 बीमारियों को हटाने पर ऐतराज जताते हुए इसे वापस सूची में शामिल करने की मांग की है।

दरअसल 2018 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना में पात्र हितग्राही को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है, हाल ही में इस योजना में 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है, इस योजना में 1760 बीमारियों का इलाज निजी अस्पतालों में करवाने की सुविधा सरकार ने दी लेकिन कुछ शिकायतों के बाद सरकार ने 196 बीमारियों को इलाज वाली

सूची से अब हटा दिया है, यानि अब इन 196 बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होगा।

निजी अस्पतालों ने 196 बीमारियों को सूची से बाहर किया

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि आयुष्मान योजना धीरे-धीरे सफ़ेद हाथी बनती जा रही है। मध्य प्रदेश में 196 बीमारियों को निजी अस्पतालों में इलाज की सूची से बाहर कर दिया गया है। दूसरी तरफ़ सरकारी अस्पतालों में उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं है। कमलनाथ ने लिखा कि मलेरिया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, छोटे बच्चों की बीमारी, बुजुर्गों की कई बीमारियाँ निजी अस्पतालों में इलाज से बाहर कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में बीमारियों को निजी अस्पतालों में उपचार से बाहर करने से आयुष्मान कार्ड धारक उपचार कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में निचले पायदान पर है और उस पर आयुष्मान कार्ड का अप्रभावी हो जाना लोक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत चिंता का विषय है।

इस विषय में गंभीरता से विचार करें मुख्यमंत्री

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की रक्षा करना और अच्छा उपचार कराना हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इस विषय में गंभीरता से विचार करें और एक कमेटी बनाकर बहुत सारी बीमारियों को दोबारा निजी अस्पतालों में उपचार के लिए खोला जाए। जो अस्पताल आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर निश्चित तौर पर सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन इस कार्रवाई का मतलब यह नहीं कि मध्य प्रदेश के ज़रूरतमंद नागरिक उपचार से वंचित कर दिए जाएं।

अवैध गौवंश तस्करी का ट्रक पेड़ से टकराया, 3 पशुओं की मौत, कई घायल

बुरहानपुर। जिले के असीरगढ़-नेपानगर मार्ग पर 12 दिसम्बर सुबह एक अवैध गौवंश तस्करी का ट्रक कबीट नाले के पास बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में 3 पशुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही निम्बोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। टीआई राहुल कामले ने बताया कि ट्रक में ठूंस-ठूंसकर गौवंश भरे गए थे। टक्कर के बाद चालक मौके से भाग गया। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से गाड़ी और पेड़ के नीचे दबे पशुओं को निकाला। घायल पशुओं को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है।

अवैध तस्करी की लगातार शिकायतें

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बुरहानपुर जिले की महाराष्ट्र सीमा से सटे होने के कारण इस क्षेत्र में अवैध गौवंश तस्करी की घटनाएं आम हैं। ग्रामीणों ने बताया कि तस्करी के दौरान पशुओं को अमानवीय तरीके से ले जाया जाता है, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक व तस्करी के नेटवर्क की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। टीआई राहुल कामले ने कहा कि पुलिस पहले भी ऐसे मामलों में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

एक वर्ष का लेखा-जोखा

सीएम के एक साल के कार्यकाल पर नेताप्रतिपक्ष ने कहा कि जो योजनाएं चल रही थी उसमें नया कुछ नहीं है, विपक्ष के मुद्दों पर सीएम ने कोई बात नहीं की है

सीएम के 1 साल की रिपोर्ट कार्ड पर नेता प्रतिपक्ष का तंज, बोले-जिन योजना में घोटाला उन पर नहीं बोले सीएम

● मंथन संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 12 दिसम्बर को सरकार के एक साल पूरा होने पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी। इसके तुरंत बाद नेता प्रतिपक्षा उमंग सिंघार ने प्रेसवार्ता कर सियासी निशाना साधा है। मुख्यमंत्री के एक साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने पर नेताप्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो योजनाएं चल रही थी उसमें नया कुछ नहीं है। जिन योजनाओं में घोटाले हुए उन पर वह मौन रहे। विपक्ष के मुद्दों पर सीएम ने कोई बात नहीं की है। चुनाव में लाडली बहना को लेकर 3000 के पोस्टर लगे लेकिन अब तक नहीं दिए गए। कब 3 हजार करेंगे उसका जवाब सीएम को देना चाहिए। इसी तरह प्रदेश में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई है। सरकार गौ माता की बात कर रही है लेकिन आज भी सड़कों पर गाये एक्सीडेंट में मर रही है, उसकी जवाबदेही सरकार ने आजतक तय नहीं की है।

अबतक बैकलॉक की नहीं हुई भर्ती

उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने एक साल में योजनाएं तक सही से नहीं चलाई है। एयर एम्बुलेंस का फायदा गरीबों को नहीं केवल अमीरों और उद्योगपतियों को इसका फायदा मिलता है। यह योजना केवल कागजों पर है। प्रदेश में अबतक बैकलॉक की भर्ती नहीं हुई न 2 लाख रोजगार दिए गए। इसी तरह अपराध को रोकने के लिए नई भर्ती की आवश्यकता है लेकिन सरकार ने अब तक भर्ती नहीं की है। ब्लॉक स्तर पर डॉक्टर्स की कमी है लेकिन घोटालों की परीक्षा करवाई जा रही है। हाइकोर्ट की फटकार के बाद भी नर्सिंग घोटाले पर कार्यवाही नहीं हुई। किसान खाद के लिए परेशान है कृषि मंत्री को खाद के मामले की जानकारी ही नहीं है।

मुख्यमंत्री ने लंदन में नहीं की किसानों की बात

उमंग सिंघार ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव लंदन गए लेकिन वहां किसानों की बात नहीं की। 60 हजार करोड़ के कौन से एमओयू साइन हुए उसकी जानकारी देना चाहिए। सरकार ने स्कूटी देने की बात की आज भी हजारों बच्चे इंतेज़ार कर रहे है। एक तरफ सरकार लोकायुक्त को काम नहीं करने देना चाहती। सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है। अधिकारियों के तबादले 3-4 बार हो रहे है। क्या बीजेपी को अधिकारियों पर विश्वास नहीं है जो बार बार ट्रांसफर किए जा रहे है। साइबर ठगी को लेकर भी अभी तक कोई ठोस कानून तैयार नहीं किया गया है। सिंगरौली देश में दूसरी नंबर पर प्रदूषित जिला है। बीजेपी विस्थापितों को समय से मुआवजा देना चाहिए। उनको उनके मूल भाव नहीं दिए जा रहे है। प्रदेश में पैसा कानून की बड़ी बात करती है लेकिन हर गांव में पुलिस पहुंच रही है। प्रदेश में लगातार कर्ज ले रहे है आर्थिक विकास को लेकर मंथन करना चाहिए।

पेज 1 का शेष

तो लालू और शरद पवार ने सही भांपा है, अब मोदी बनाम दीदी ही होने वाला है.....

...फिर भी इंडिया ब्लॉक कर रहा संघर्ष

जबकि इंडिया ब्लॉक के लिए यह सबसे अच्छी स्थिति नहीं बन पाई, लेकिन सबसे खराब स्थिति यानी विघटन भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल कर एक मजबूत संसदीय विपक्ष का नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य जगहों पर प्रमुख क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी के चुनावी रथ के खिलाफ अपनी जमीन मजबूत की। झारखंड और जम्मू-कश्मीर ने बीजेपी के लिए बहुत निराशाजनक रूप से इंडिया ब्लॉक के पक्ष में मतदान किया। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, फिर भी खराब प्रदर्शन करने वाला विपक्ष संघर्ष कर रहा है।

आज की राजनीति में बीजेपी हावी

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी आज राजनीति पर हावी है। लोकप्रिय वोट के 2/5 हिस्से से थोड़ा कम के साथ, यह शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। कुल मिलाकर, यह कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, आप और वामपंथी दलों की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर डाले गए वोटों के बराबर है। खास बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में एक चौथाई मतदाताओं ने न तो एनडीए और न ही इंडिया ब्लॉक को पसंद किया। इसलिए, संक्षेप में, बीजेपी, सबसे बड़ा राजनीतिक ब्रांड हो सकती है लेकिन 60 प्रतिशत से अधिक मतदाता गैर-बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ईवीएम बटन दबाते हैं।

विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती: विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करना है। सिद्धांत रूप में, इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में एकजुट विपक्षी उम्मीदवार सुनिश्चित करने के लिए होशियारी से सीट-बंटवारे की रणनीति की आवश्यकता होती है। दो घोड़ों की दौड़ में जीत की सीमा को 51 प्रतिशत तक बढ़ाकर, एक एकीकृत विपक्ष बीजेपी को अतिरिक्त वोटों के लिए संघर्ष करने की चुनौती देगा, खासकर महिलाओं के बीच। लेकिन, जैसा कि हमने इस साल देखा है, छोटी पार्टियां और निर्दलीय बीजेपी की जीत की सीमा को मैनेज करने वाले स्तर तक कम कर सकते हैं।

कांग्रेस का स्ट्राइक रेट चिंताजनक

इन परिस्थितियों में, इंडिया ब्लॉक के दलों के सामने एक दुविधा है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन उसने 326 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से एक तिहाई से भी कम सीटें जीतीं। इस शरद ऋतु में राज्य चुनावों में, इसका स्ट्राइक रेट छठे स्थान पर आ गया। स्पष्ट रूप से, कांग्रेस जितनी सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए, उससे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है। साथ ही इसके क्षेत्रीय सहयोगी भविष्य में अधिक संतुलित सीट-बंटवारे के लिए सही मोलभाव कर रहे हैं। अगले 18 महीनों में चुनाव होने वाले राज्यों - दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल - में क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की कीमत पर बहुत कुछ हासिल करना है।

तो अलग होता 2024 का चुनाव: इस लोकसभा में कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक का सूत्रधार बनना सीखना होगा। अगर पिछली सर्दियों में ऐसा किया होता, तो नीतीश कुमार को वह नेतृत्व पद मिल सकता था जिसकी उन्हें चाहत थी और 2024 का चुनाव अलग तरह से होता। राहुल गांधी की लोकप्रिय यात्राओं और उनकी बहन प्रियंका के पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ के रूप में पदार्पण ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा हो सकता है, लेकिन पार्टी के बचे रहने को पुनरुत्थान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

जारी रहेगा गिरावट का रुझान: कांग्रेस को अब नियमित रूप से सपा और एनसीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों से वोट ट्रांसफर मिलते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसका जवाब मिलता है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच, कांग्रेस ने गठबंधन सहयोगियों को लगभग 100 सीटें छोड़ दीं, लेकिन 543 में से 326 सीटें अभी भी बहुत अधिक लगती हैं। यह गिरावट का रुझान जारी रहने की संभावना है, खासकर उन राज्यों में जहां अन्य इंडिया ब्लॉक की सहयोगी पार्टियों का दबदबा है।

ममता जैसी गैर-कांग्रेसी राजनीतिज्ञ के नेतृत्व में गठबंधन में शक्ति का एक नया संतुलन स्थापित होगा। पूरे भारत में गैर-बीजेपी वोट को एकजुट करने के लिए, विपक्ष को कांग्रेस के लिए उपलब्ध सीटों के अनुपात को सीमित करना होगा। वर्तमान में गठबंधन की तरफ से जीती गई संसदीय सीटों में से 42 प्रतिशत सीटें कांग्रेस के पास हैं। इस अनुपात का मतलब होगा कि 2029 तक इंडिया ब्लॉक के भागीदारों को 100 सीटें और देनी होंगी।

राज्य के चुनावों में दिखेगा असर: चुनाव वाले राज्यों में, पतन और भी अधिक होगा। बिहार में, कांग्रेस ने 2020 में महागठबंधन को चुनाव में नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस ने 70 सीटों में से मात्र 19 सीटें जीती थीं। वहीं, आरजेडी ने 144 में से 75 और सीपीआई (एमएल) ने 19 में से 12 सीटें जीतीं। यदि 2025 में सीटों का बंटवारा इंडिया ब्लॉक के भागीदारों की तरफ से सीटों के अनुपात के अनुसार होता है, तो कांग्रेस 243 विधानसभा सीटों में से केवल 45 पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में भी, उसे योगी सरकार को गिराने के लिए समाजादी पार्टी की योजनाओं का सहारा लेना पड़ सकता है।

दिल्ली और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की संभावनाएं बहुत खराब हैं। आप और टीएमसी बहुत कुछ स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और किसी महत्वपूर्ण तीसरे दल के बिना अकेले ही बीजेपी से लड़ने का इरादा रखते हैं। कांग्रेस को जो भी पेशकश की जाती है उसे पार्टी या तो स्वीकार कर सकती है या अकेले चुनाव लड़कर सहयोगियों के गुस्से का सामना कर सकती है। ममता के इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने के बाद, दूसरा विकल्प कम संभावना वाला है।

2024 की गलतियों से सबक...

अगर इंडिया ब्लॉक को 2024 में अपनी गलतियों से सीखना है, तो गैर-कांग्रेसी अध्यक्ष का होना एक स्वागत योग्य कदम होगा। गठबंधन में सबसे सफल भाजपा विरोधी रणनीतिकार ममता बनर्जी अब नेतृत्व करने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में हैं। एक अनुभवी राजनीतिज्ञ के रूप में उनका कौशल सहयोगियों के बीच सहज संचार सुनिश्चित कर सकता है। साथ ही उनकी श्रेष्ठता कांग्रेस को नेतृत्व करने से रोके बिना सूत्रधार के रूप में रख सकती है। चाहे एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक, मोदी का उत्तराधिकारी लुटियंस दिल्ली से आने की संभावना कम है, बल्कि देश के किसी गतिशील राज्य से आने की संभावना कम है। क्या गुजरात का विकास मॉडल बंगाल के कल्याण मॉडल को रास्ता देगा?